# रक्षा लेखा महानियंत्रक

### Controller General of Defence Accounts उलान बटार रोड, पालम, दिल्ली कैंट 110010 Ulan Batar Road, Palam, Delhi Cantt- 110010

सं. प्रशा./XIV/14164/सातवाँ के. वे. आ./परिपत्र/जिल्द-। No. AN/XIV/14164/VIIth CPC/Circular/VoI-I

दिनांक 05/04/2017

सेवा में,

सभी र.ले.प्र.नि./प्र.ले.नि./प्र.ले.नि.(फै.)/ र.ले.नि.(आईटी एवं एसडीसी), हैदराबाद All PCsDA/CsDA/PCA (Fys)/CDA (IT&SDC), Hyderabad

विषय: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता प्रदान करना- 01.01.2017 से लागू संशोधित दरें । Sub: Grant of dearness allowance to Central Government employees - Revised Rates effective from .01.01.2017.

उपर्युक्त विषय पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के दिनांक 30.03.2017 के कार्यालय ज्ञापन सं॰ 1/3/2017-ई.II(बी), जो कि वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग की वैबसाइट से डाउनलोड किया गया है, की प्रति सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है ।

A copy of Government of India, Ministry of Finance (Department of Expenditure) Office Memorandum No. 1/3/2017-E\_II (B) dated 30.03.2017 on the above subject, which is downloaded from the website of Mof, DoE, is attached for your information, guidance and necessary action please.

संलग्नक: यथोपरि

किर्विता गर्ग

रक्षा लेखा वरिष्ठ उप महानियंत्रक(प्रशा)

#### प्रतिलिपि:-

- 1. प्रशासन-4।
- 2. लेखा परीक्षा 1, 2 एवं 4 (स्थानीय) ।
- 3. लेखा परीक्षा (समंवय) अनुभाग (स्थानीय) ।
- 4. आई.टी. एवं एस. विंग(स्थानीय) :- रक्षा लेखा महानियंत्रक वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
- 5. प्रशिक्षण एवं संगोष्ठी केंद्र, बरार स्क्वायर, दिल्ली छावनी ।
- 6. प्स्तकालय अन्भाग (स्थानीय) ।
- 7. मास्टर नोट बुक प्रशासन-14 ।
- 8. महासचिव, ए.आई.डी.ए.ए. (सी.बी.) पुणे {द्वारा रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (अधिकारी) पुणे} ।
- 9. महासचिव, ए.आई.डी.ए.ई.ए. (म्॰) कोलकाता {द्वारा प्रधान नियंत्रक लेखा (फेक्ट्री) कोलकाता} ।

कविता गर्ग)

रक्षा लेखा वरिष्ठ उप महानियंत्रक(प्रशा)

130

सं. 1/3/2017-ई.П(बी)

भारत सरकार वित्त मंत्रालय व्यय विभाग

> नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली 30 मार्च, 2017

## कार्यालय ज्ञापन

विषयः केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता प्रदान किया जाना - 01.01.2017 से लागू संशोधित दरें।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के 4 नवंबर, 2016 के का. ज्ञा. सं. 1/2/2016-ई.II(बी) के संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रपति ने सहर्ष यह निर्णय लिया है कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ता 01 जनवरी, 2017 से मूल वेतन के 2 % की विद्यमान दर से बढ़ाकर 4% कर दिया जाएगा।

- 2. संशोधित वेतन संरचना में 'मूल वेतन' शब्द का अभिप्राय सरकार द्वारा स्वीकृत 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित लेवल में आहरित वेतन से है किन्तु इसमें विशेष वेतन आदि जैसा अन्य प्रकार का कोई वेतन शामिल नहीं है।
- 3. यह महंगाई भत्ता, पारिश्रमिक का एक भिन्न कारक बना रहेगा और इसे एफआर 9(21) के तहत वेतन नहीं माना जाएगा।
- 4. महंगाई भत्ते की मद में 50 पैसे और उससे अधिक के अंश का भुगतान अगले उच्चतर रुपए के पूर्णांक में किया जाए और 50 पैसे से कम अंश को नजरअंदाज किया जाए।
- 5. मंहगाई भत्ते की बकाया राशि का भुगतान मार्च, 2017 के वेतन के संवितरण की तारीख से पहले नहीं किया जाएगा।
- 6. ये आदेश, रक्षा सेवा प्राक्कलनों से वेतन प्राप्त करने वाले असैनिक कर्मचारियों पर भी लागू होंगे और यह व्यय, रक्षा सेवा प्राक्कलनों के संगत शीर्ष के नामे डाला जाएगा। सशस्त्र बल कर्मियों और रेलवे कर्मचारियों के संबंध में क्रमशः रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।
- 7. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सहमित से जारी किए जाते हैं।

30/03)2017 (निर्मला देव)

उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में

प्रतिलिपिः

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार)। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि। No. 1/3/2017-E-II (B) Government of India Ministry of Finance Department of Expenditure

North Block, New Delhi Dated the 30<sup>th</sup> March, 2017.

#### OFFICE MEMORANDUM

Subject: Grant of Dearness Allowance to Central Government employees - Revised Rates effective from 1.1.2017.

The undersigned is directed to refer to this Ministry's Office Memorandum No. 1/2/2016-E-II (B) dated 4<sup>th</sup> November, 2016 on the subject mentioned above and to say that the President is pleased to decide that the Dearness Allowance payable to Central Government employees shall be enhanced from the existing rate of 2% to 4% of the basic pay with effect from 1<sup>st</sup> January, 2017.

- 2. The term 'basic pay' in the revised pay structure means the pay drawn in the prescribed Level in the Pay Matrix as per 7<sup>th</sup> CPC recommendations accepted by the Government, but does not include any other type of pay like special pay, etc.
- 3. The Dearness Allowance will continue to be a distinct element of remuneration and will not be treated as pay within the ambit of FR 9(21).
- 4. The payment on account of Dearness Allowance involving fractions of 50 paise and above may be rounded to the next higher rupee and the fractions of less than 50 paise may be ignored.
- 5. The payment of arrears of Dearness Allowance shall not be made before the date of disbursement of salary of March, 2017.
- 6. These orders shall also apply to the civilian employees paid from the Defence Services Estimates and the expenditure will be chargeable to the relevant head of the Defence Services Estimates. In respect of Armed Forces personnel and Railway employees, separate orders will be issued by the Ministry of Defence and Ministry of Railways, respectively.
- 7. In so far as the employees working in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders are issued with the concurrence of the Comptroller and Auditor General of India.

( Nirmala Dev)

Deputy Secretary to the Government of India

To

All Ministries/Departments of the Government of India (as per standard distribution list).

Copy to: C&AG, UPSC, etc.